



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2004/श्रावण 1, 1926

No. 648]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2004/SRAVANA 1, 1926

वित्त मंत्रालय

(सकल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2004

का.आ. 839(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 अप्रैल, 2005 से मूल्यवर्धित कर प्रणाली के सुगमता से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए 17 जुलाई, 2004 से एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करती है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (i) डॉ. गोविन्द राव, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान।
- (ii) श्री पी. वी. राजारमन, पूर्व वित्त सचिव, तमिलनाडु सरकार।
- (iii) श्री रमेश चन्द्र, सदस्य-सचिव, राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति।
- (iv) डॉ. रेणुका विश्वनाथन, सलाहकार, योजना आयोग।
- (v) श्री सी. एम. बछावत, वाणिज्य कर आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार।
- (vi) श्री एम. एन. जोशी, अपर सचिव, वित्त, गुजरात सरकार; और
- (vii) सुश्री आर. कविता राव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान।

निदेशक, राज्य कर, वित्त मंत्रालय समिति के संयोजक होंगे।

समिति के विचारार्थ विषय होंगे :—

- (i) मूल्यवर्धित कर, राजस्व बढ़ाने वाला है, यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय।
 - (ii) मूल्यवर्धित कर के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि, यदि कोई हो, के लिए राशियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त और स्तर।
 - (iii) मूल्यवर्धित कर के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार के लिए अपेक्षित नीति।
 - (iv) संक्रमणकालीन मुद्दे जो मूल्यवर्धित कर प्रणाली (प्रशासनिक और कानून मुद्दे) को लागू करने के संदर्भ में उठेंगे।
 - (v) केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के तरीके।
2. इसके अतिरिक्त, समिति वित्त मंत्रालय के माध्यम से राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा समिति को भेजे गए किसी अन्य मुद्दे को ले सकती है। यह अतिरिक्त सदस्य, यदि अपेक्षित हों, को भी सहयोजित कर सकती है।
 3. समिति प्रारम्भ में 30 जून, 2005 तक नियुक्त की जाती है और उसके बाद इसकी अवधि राज्य सरकारों की अपेक्षाओं के आधार पर और आगे बढ़ाई जा सकेगी।

[पत्र. सं. 21/1/2004-बिक्री कर]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2004

S.O. 839(E).—The Central Government hereby constitutes a Technical Experts Committee with effect from 17th July, 2004 to work closely with State Governments for smooth implementation of VAT from April 1, 2005. The Committee will consist of the following Members :—

- (i) Dr. Govinda Rao, Director, National Institute of Public Finance and Policy.
- (ii) Shri P.V. Rajaraman, Ex-Finance Secretary, Government of Tamil Nadu.
- (iii) Shri Ramesh Chandra, Member-Secretary, Empowered Committee of State Finance Ministers.
- (iv) Dr. Remka Vishwanathan, Adviser, Planning Commission.
- (v) Shri C.M. Bachhawat, Commissioner, Commercial Taxes, Government of West Bengal.
- (vi) Shri M.N. Joshi, Addl. Secretary, Finance, Government of Gujarat; and
- (vii) Ms. R. Kavita Rao, Fellow, National Institute of Public Finance and Policy.

The Director, State Taxes, Ministry of Finance shall be the Convenor of the Committee.

The terms of reference of the Committee will be :—

- (i) Steps to ensure that VAT is revenue enhancing.
 - (ii) Principles and levels of compensation to be paid to States for revenue loss, if any, because of the implementation of VAT.
 - (iii) Strategy required for education, training and publicity for implementation of VAT.
 - (iv) Transitional issues which will emerge in the context of switchover to VAT (administrative and legal issues).
 - (v) Modalities for phasing out Central Sales Tax.
2. In addition, the committee could take up any other issue referred to it by the Ministry of Finance or the Empowered Committee of State Finance Ministers through the Ministry of Finance. It can also co-opt additional members if required.
 3. The committee is initially appointed up to June 30, 2005 and its period could be further extended thereafter on the basis of the requirements of the State Governments.

[F. No. 21/1/2004-ST]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.